>

Title: Situation arising out of cancellation of trains due to agitation by Akhil Bhartiya Jat Mahasabha.

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): सभापति महोदया, मैं आपका आभारी हूं कि आपने एक अत्यंत महत्वपूर्ण और ज्वलंत समस्या के संबंध में मुझे अपनी बात रखने का अवसर दिया है। पिछले शनिवार से लखनऊ से दिल्ली वाया मुरादाबाद की रेल लाइन पर ट्रैक जाम होने के कारण आवागमन पूरी तरह से ठप्प है। उसके कारण 80 रेलगाड़ियां जो देश की राजधानी दिल्ली को जोड़ने का काम करती थीं, जिनमें लोगों ने सुप्रीम कोर्ट, आल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट या अन्य जगह आवश्यक कामों के लिए आरक्षण करवा रखे थे, आज उन्हें वहां पहुंचने में काफी कठिनाई हुई। मुद्दा आरक्षण का है। निश्चित तौर से जो आरक्षण समर्थक ट्रैक पर बैठे हुए हैं, उनका मुद्दा महत्वपूर्ण है। हरियाणा के मुख्य मंत्री ने भी जाटों के आरक्षण के संबंध में भारत सरकार को पत्र लिखा था। केन्द्र सरकार ने उसे पिछड़ा वर्ग आयोग को विचार करने के लिए दिया है। एक तरफ पिछड़ा वर्ग आयोग के समक्ष उस आरक्षण का मामला लंबित है और दूसरी तरफ आज ममता जी ने रेल बजट पर रिप्लाई देते समय यह बात कही थी कि रेलवे ट्रैक को सबसे साफ्ट टारगेट माना जाता है। उसमें आए दिन कहीं गुर्जर आन्दोलन, कहीं किसान आन्दोलन, कहीं जाट आन्दोलन, कहीं छत्तीसगढ़, झारखंड में माओवादी आन्दोलन होते हैं जिनके कारण रेलवे का लगभग दो हजार करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।

उन्होंने अपील की कि जिन राज्यों में इस तरह के ट्रैक जाम नहीं होंगे, रेल की सुविधा होगी, वहां हम दो नयी रेलगाड़ियां चलाने के लिए बजट में शामिल करेंगे। उस राज्य की आवश्यकताओं की मांग के अनुरूप हम उसे एक रेल परियोजना देंगे। जहां भारत सरकार के रेल मंत्री जी ने इस बात का आश्वासन दिया, पिछले तीन दिनों से उस रेल ट्रैक पर लोगों द्वारा जाम किया गया, जिसके कारण शनिवार को 21 ट्रेनें और सोमवार को दस ट्रेनें रद्द की गयीं। ...(व्यवधान) हमारे सांसद चूंकि मुरादाबाद के हैं, वहां लाइनें उखाड़ दी गयीं। यह कितनी बड़ी राष्ट्रीय क्षति है। 51 ट्रेनें डायवर्ट की गयीं, जो लखनऊ से अब सहारनपुर हो कर आ रही हैं जैसे हापुड़, पिलकुवा या काफूपुरा पर ट्रैक जाम है।

मैं समझता हूं कि इससे लाखों लोग प्रभावित हैं। यह अत्यंत लोक महत्व का विषय है, इसलिए राज्य सरकार को भी इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। वहां तीन दिनों से लोग हड़ताल पर बैठे हैं और उन्होंने ट्रैक जाम कर रखा है। वह ट्रैक 24 घंटे तक जाम है, लेकिन राज्य सरकार द्वारा उनको उस ट्रैक से हटाने का कोई प्रयास नहीं हो रहा है। आज आरक्षण का वह मामला पिछड़ा वर्ग आयोग के समक्ष लंबित है, तो पिछड़ा वर्ग आयोग को पैरवी करनी चाहिए। जब पिछड़ा वर्ग आयोग उस पर विचार करके सामयिक रूप से अपनी संस्तुतियां भारत सरकार को भेजेगा, तभी भारत सरकार उस पर विचार कर सकती है।

आज हम इस बात के कायल हैं कि जहां आरक्षण की मांग उठती है, तो हम सत्याग्रह और प्रजातांत्रिक माध्यम से अपनी बात को पुरजोर ढंग से कह सकते हैं। लेकिन उस आरक्षण के सवाल पर अगर पूरे देश की राजधानी को चाहे वह लखनऊ हो, दिल्ली हो या हिसार की तरफ जाने वाली हो, अब यह भी हुआ कि 9 तारीख को पूरी दिल्ली का घेराव करने की तैयारी है, तो इससे आम जन-जीवन प्रभावित होता है। आज आम जन-जीवन में कठिनाइयां उत्पन्न हो रही हैं और पिछले तीन दिनों से देश की 80 ट्रेनें प्रभावित हो रही हैं। इससे लोग राजधानी में आने में विलंबित हो रहे हैं।

मैं समझता हूं कि यह अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं अपील करना चाहूंगा कि देश के उन लाखों यात्रियों की सुविधाओं को देखते हुए, उनकी आवश्यकताओं को देखते हुए, उनकी इमर्जेंसी यात्राओं को देखते हुए कम से कम रेल यात्रा बहाल होनी चाहिए और उस ट्रैक को खाली कराना चाहिए। जहां तक आरक्षण का सवाल है, तो उसकी क्या अद्यतन स्थिति है या उसमें पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा क्या प्रगति हुई है, उस संबंध में जो कार्रवाई होनी चाहिए, उसे भी करने की आवश्यता है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं कहना चाहूंगा कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय को उठाने की अनुमति दी, उसके लिए धन्यवाद।